उत्पादों में होंगे नमक और चीनी कम

एचयूएल, नेस्ले और पतंजलि ने इन चीजों के इस्तेमाल में खासी कमी की घोषणा की

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 10 जुलाई

एफएमसीजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों ने अपने उत्पादों में नमक, चीनी और ट्रांस फैट में कमी लाने का वादा किया है। नेस्ले व आईटीसी से लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि जैसी फर्मों ने आने वाले समय में अस्वास्थ्यकर तत्वों में 5 से 50 फीसदी तक की कमी लाने का भरोसा दिलाया है, जो खाद्य नियामक एफएसएसएआई की उस पहल के मुताबिक होगा, जिसमें नियामक ने स्वास्थ्यकर खाद्य को प्रोत्साहित करने की बात कही है।

एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया और आईटीसी जैसी एफएमसीजी कंपनियां कुछ समय से नमक व चीनी के इस्तेमाल में कमी लाने पर काम कर रही है, लेकिन आज की प्रतिबद्धता इसे अगले स्तर पर ले जाने की वैयक्तिक कोशिश को लक्षित है। खाद्य व बेवरिजेज क्षेत्र की 10 कंपनियों के अधिकारी आज दिल्ली में एफएसएसएआई के मुख्यालय में इकट्ठा हुए और ईटिंग राइट मूवमेंट को अपना समर्थन दिया, जो खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने अन्य हितधारकों मसलन रेस्तरां व ईटरीज आदि को शामिल करने के लिए पेश किया है।

देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर अपनी 75 फीसदी उत्पादों में नमक की मात्रा घटाकर पांच ग्राम प्रतिदिन के स्तर पर लाएगी, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 तक ऐसा करना तय किया है। यह जानकारी एचयूएल के कार्यकारी निदेशक सुधीर सीतापति ने दी। फर्म ने बच्चों की आइसक्रीम में चीनी की मात्रा घटाने की प्रतिबद्धता जताई। खाद्य व बेवरिजेज में राजस्व के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले का इरादा चीनी की मात्रा छह फीसदी, नमक की मात्रा 10 फीसदी और वसा की मात्रा 2.5 फीसदी घटाने की है और यह साल 2017 के स्तर के मुकाबले साल 2020 तक घटाया जाएगा। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक सुरेश नारायणन ने कहा, नेस्ले ने हालांकि सालों से इसके इस्तेमाल में कमी लाई है, लेकिन हालिया प्रतिबद्धता पिछली कोशिशों को और आगे बढ़ाएगी। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी ने कहा, हम लगातार पोषकता के रोडमैप पर काम कर रहे हैं ताकि पोर्टफोलियो को और स्वास्थ्यकर बनाया जा सके। फर्म ने साल 2020 तक अपने पोर्टफोलियो में चीनी व नमक की मात्रा 5 फीसदी तक घटाएगी।

डेल मोंटे ने चीनी, नमक और वसा की मात्रा साल 2025 तक अपने उत्पादों में 20 से 30 फीसदी तक घटाने का इरादा जताया है, वहीं केलॉग्स ने रेडी टु ईट उत्पादों में चीनी व नमक की मात्रा 2020 तक 10 से 30 फीसदी तक घटाने की बात कही है। मैरिको ने कहा कि वह नए उत्पादों मसलन सफोला मस्टर्ड ओट्स में नमक की मात्रा साल 2020 तक 15 फीसदी घटाएगी। पतंजलि ने कहा कि वह चीनी मुक्त च्यवनप्राश उतारेगी और उसका इरादा अपने मौजूदा च्यवनप्राश में चीनी की मात्रा 3 से 5 फीसदी तक घटाने का है। आईटीसी के फूड डिविजन के मुख्य कार्याधिकारी हेमंत मलिक के मुताबिक, कंपनी के 75 फीसदी नूडल्स व स्नैक्स पोर्टफोलियो में साल 2023 तक नमक की मात्रा 10 फीसदी घटाई जाएगी। ऐसा ही कदम बेवरिजेज पोर्टफोलियो में भी उठाया जाएगा।

क्राफ्ट हाइंज का इरादा साल 2025 तक टोमैटो केचअप में चीनी की मात्रा 50 फीसदी घटाने का है।

स्वस्थ जीवन की ओर

- एचयूएल अपने **75** फीसदी खाद्य व बेवरिजेज **2020** तक डब्ल्यूएचओ के बेंचमार्क के हिसाब से नमक की मात्रा घटाएगी
- नेस्ले का इरादा चीनी की मात्रा छह फीसदी, नमक की मात्रा **10** फीसदी और वसा की मात्रा **2.5** फीसदी घटाने का है
- ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज साल **2020** तक अपने पोर्टफोलियो में चीनी व नमक की मात्रा **5** फीसदी तक घटाएगी
- आईटीसी अपने **75** फीसदी नूडल्स व स्नैक्स पोर्टफोलियो में साल **2023** तक नमक की मात्रा **10** फीसदी घटाएगी
- पतंजलि अपने मौजूदा च्यवनप्राश में चीनी की मात्रा **3** से **5** फीसदी तक घटाएगी
- केलॉग्स, डेल मोंटे, क्राफ्ट हाइंज, मैरिको ने भी एफएसएसएआई के ईटिंग राइट मूवमेंट के हिसाब से नमक, चीनी व वसा की मात्रा घटाने का इरादा जताया

पीएनबी-कार्लाइल बेचेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस का हिस्सा

अद्वैत राव पलेपू
मुंबई, 10 जुलाई

पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस ने आज स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना दी कि उसकी दो प्रवर्तक कंपनियां- पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) और दी कार्लाइल ग्रुप इस हाउसिंग फाइनैंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती हैं।

कंपनी में पीएनबी की हिस्सेदारी 32.79 फीसदी और कार्लाइल की सहायक कंपनी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स की 32.36 फीसदी हिस्सेदारी है। दोनों प्रवर्तक कंपनियों ने पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस में कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस के प्रबंधन से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

कार्लाइल समूह एक वैश्विक निवेश कंपनी है, जिसके पास 201 अरब डॉलर की संपत्तियां हैं और उसे वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, परिवहन, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे 10 क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई.आई.एम.रोड, लखनऊ–226013 (उ0प्र0)
प्रबन्धन विकास कार्यक्रम
जानकारी के लिए फोन नं0: 0522–6696282–3/8 पर संपर्क करें या mdpoffice@iiml.ac.in; mdp@iiml.ac.in पर मेल करें। कृपया हमारी वेबसाइट http://www.iiml.ac.in/mdpcal का निरीक्षण करें।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई.आई.एम.रोड, लखनऊ–226013 (उ0प्र0)
व्यापार के लिए विवरण अध्ययन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम
के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
(3 दिनों के 4 शिक्षण भागों में 80 घंटों का शिक्षण होगा)
विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र http://www.iiml.ac.in/lmdpcal से डाउनलोड किये जा सकते हैं। विवरण हेतु दूरभाष सं. (0522) 6696287–88, 82, 83 पर संपर्क करें अथवा lmdpoffice@iiml.ac.in या lmdpchair@iiml.ac.in पर ई–मेल करें।

इंडसइंड बैंक का मुनाफा 24 फीसदी बढ़ा

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक का शुद्ध लाभ जून 2018 में समाप्त तिमाही में 23.8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 10.35 अरब रुपये पर पहुंच गया। मुख्य रूप से ब्याज आय में बढ़ोतरी से बैंक के मुनाफे में इजाफा हुआ। पिछले साल की समान अवधि में बैंक ने 8.36 अरब रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था।

इंडसइंड के मुख्य कार्याधिकारी व प्रबंध निदेशक रोमेश सोबती ने कहा, तिमाही के दौरान हमारे लाभ पर सराकरी प्रतिभूतियों का असर पड़ा, जो 50 आधार अंक तक फिसल गया। इससे पूरे बैंकिंग क्षेत्र के लाभ पर भी असर पड़ा है। हमारा मार्क टु मार्केट नुकसान 86 करोड़ रुपये रहा है और इसके लिए हमने प्रावधान किया है।

तिमाही में बैंक की कुल आय 20 फीसदी बढ़कर 63.93 अरब रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 53 अरब रुपये रही थी। इसकी शुद्ध ब्याज आय 21.1 अरब रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20 फीसदी ज्यादा है। *बीएस*

आईडीबीआई की रेटिंग पर मालिकाना हक में बदलाव का असर नहीं : इक्रा

अभिजित लेले
मुंबई, 10 जुलाई

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने आज मालिकाना हक में बदलाव के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक की रेटिंग में किसी तरह के बदलाव की संभावना से इनकार किया। रेटिंग में किसी तरह के बदलाव के लिए बैंक के एकल प्रोफाइल में सुधार तक इंतजार करना होगा।

इसकी हिस्सेदारी का अधिग्रहण एलआईसी की तरफ से किए जाने से निकट भविष्य में आईडीबीआई बैंक का क्रेडिट प्रोफाइल आगे बढ़ेगा। यह तभी होगा जब बैंक के एकल प्रोफाइल में सुधार होगा।

मौजूदा रेटिंग सॉवरिन समर्थन को समायोजित करता है। भारत सरकार इस बैंक की प्रवर्तक है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे में है और इसकी वजह इसके फंसे कर्ज का स्तर बहुत ऊंचा रहना है।

इक्रा के प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र की रेटिंग्स) अनिल गुप्ता ने कहा, आईडीबीआई की हिस्सेदारी का अधिग्रहण एलआईसी के पॉलिसीधारकों के खाते के तहत होने की संभावना है। ऐसे में बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी इसे एलआईसी की सहायक नहीं बनाएगा।

इसके अलावा पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश होने के नाते यह हिस्सेदारी अस्थायी प्रकृति की होगी और एलआईसी को आने वाले समय में बैंक की हिस्सेदारी घटाकर 15 फीसदी करनी होगी, जो नियामकीय अनिवार्यता है।

भविष्य के नुकसान की भरपाई और बैंक के लाभ को बहाल करने की खातिर बढ़त को सहारा देने के लिए पूंजी का निवेश बैंक के एकल प्रोफाइल के लिए सकारात्मक होगा। साथ ही गुप्ता ने कहा कि लंबी अवधि के मालिकाना हक के ढांचे के लिए एलआईसी व भारत सरकार का इरादा रेटिंग को आगे बढ़ाने के लिए अहम होगा।

29 जून 2018 को बीमा नियामक आईआरडीएआई ने एलआईसी की तरफ से आईडीबीआई बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। एलआईसी के पास पहले से ही इसकी 7.98 फीसदी हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी निकट भविष्य में बढ़ाकर 51 फीसदी करने का प्रस्ताव है।

एचडीएफसी समूह का एमकैप10 लाख करोड़ रु. के पार

दीपक पारिख के नेतृत्व वाले एचडीएफसी वित्तीय सेवा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण आज 10 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। टाटा समूह के बाद यह दूसरा कंपनी समूह है, जिसका बाजार पूंजीकरण इस आंकड़े के पार पहुंचा है। एचडीएफसी समूह में इस समय चार सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। आवास वित्त पोषण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, बैंकिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एचडीएफसी बैंक, जीवन बीमा क्षेत्र की एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ और गृह फाइनैंस इस समूह में शामिल हैं। दूसरी तरफ टाटा समूह की करीब 30 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। शेयर बाजारों में आज कारोबार की समाप्ति पर एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 5,59,633.53 करोड़ रुपये, एचडीएफसी लिमिटेड का 3,26,776.81 करोड़ रुपये, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 95,936.72 करोड़ रुपये और गृह फाइनैंस का बाजार पूंजीकरण 24,967.71 करोड़ रुपये रहा। *एजेंसियां*

सेल-आर्सेलर का संयुक्त उद्यम 30 साल के उपबंध पर फंसा

ज्योति मुकुल और मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 10 जुलाई

विशेषीकृत स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल संग सेल का संयुक्त उद्यम 30 साल तक इस अनुबंध से बाहर न निकलने के उपबंध के चलते अटका हुआ है और इसी उपबंध के चलते सेल इसमें आगे बढ़ने को अनिच्छुक नजर आ रही है। संयुक्त उद्यम पर तीन साल के बात हो रही है, लेकिन दोनों स्टील दिग्गज अभी तक औपचारिक समझौता नहीं कर पाए हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ऐसे संयुक्त उद्यम में वक्त लगता है क्योंकि इससे कई वाणिज्यिक मसले जुड़े होते हैं। चूंकि संयुक्त उद्यम लंबी अवधि का होगा, लिहाजा आपको काफी सावधान रहना होगा मसलन अभी की कौन सी चुनौतियां हैं और संयुक्त उद्यम की पूरी अवधि के दौरान बाजार कैसा रहेगा ताकि यह लाभकारी हो।

संपर्क किए जाने पर सेल के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। आर्सेलरमित्तल लंबी अवधि का बाध्यकारी अनुबंध चाहती है और इसकी समाप्ति पर दोनों कंपनियां यह फैसला ले पाएंगी कि इस उद्यम को जारी रखना है या नहीं।

सूत्र ने कहा, ऑटो ग्रेड स्टील का विस्तार दुनिया भर की काफी कम कंपनियों के बीच है। यह काफी संरक्षित बाजार है और जब हमने इस तरह के उत्पाद विकसित किए तो तकनीक देने वाली कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जल्द हम इससे निकासी न करें क्योंकि इसे विकसित करने में काफी वक्त लगता है और काफी रकम खर्च होती है।

संयंत्र के लिए करीब 300 एकड़ जमीन की दरकार है, लेकिन जमीन कोई मसला नहीं है। 30 लाख टन के संयुक्त उद्यम के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। मंत्रालय को उम्मीद है कि 1 अरब डॉलर की प्रस्तावित साझेदारी को अगले कुछ महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, दोनों कंपनियां संयुक्त उद्यम की जांच कर रही है। ज्यादातर चीजों पर दोनों पक्षकारों की सहमति है।

यह इकाई गुजरात या महाराष्ट्र में स्थापित हो सकती है। चूंकि यह इकाई ऑटोमोटिव स्टील बनाएगी, लिहाजा ऑटो केंद्र के तौर पर महाराष्ट्र में पुणे-चाकन का इलाका और गुजरात में साणंद पर विचार कर रहा है।

प्रस्तावित संयुक्त उद्यम सेल के राउरकेला संयंत्र के साथ हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिप की सोर्सिंग के लिए लंबी अवधि का खरीद अनुबंध करेगा। संयुक्त उद्यम संयंत्र में वैल्यू एडिशन के जरिए ऑटोमोटिव स्टील का उत्पादन किया जाएगा।

अब भी हो रही है बातचीत

- यह संयुक्त उद्यम भारत में ऑटोमोटिव स्टील निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए था
- **30** लाख टन क्षमता वाली संयुक्त उद्यम इकाई के लिए साइट की पहचान कर ली गई है
- **30** साल के अनुबंध में बाध्यकारी उपबंध पर फर्में अब भी बातचीत कर रही हैं
- आर्सेलरमित्तल और सेल ने मई **2015** में प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे

भूषण पावर के बैंकों ने अगले हफ्ते के लिए फैसला टाला

दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही भूषण पावर ऐंड स्टील के लेनदारों ने तरजीही बोलीदाता के चयन पर फैसला अगले हफ्ते के लिए टाल दिया है। लेनदारों ने कहा, लेनदारों की समिति की सोमवार को बैठक हुई और इसमें लेनदार विभाजित नजर आए। ज्यादातर लेनदार टाटा स्टील के पक्ष में थे, वहीं कुछ लेनदारों को लगा कि लिबर्टी हाउस की बोली पर भी नजर डाली जानी चाहिए, खास तौर से नैशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में कंपनी की अपील को देखते हुए।

सूत्रों ने कहा, इसके हिसाब से आज फैसला होना था, जिसे अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया। लेनदारों की समिति मोटे तौर पर 16 जुलाई को बैठक करेगी। *बीएस*

विजया बैंक
प्रधान कार्यालय, 41/2, एम जी रोड, बेंगलूर–560001, फोन: 080 25584066
ई-मेल : hrd@vijayabank.co.in
वेबसाइट : www.vijayabank.com

समाप्ति सूचना

यह, उन 03 कर्मचारियों (जिनकी सूची बैंक की वेबसाइट में अपलोड की गई है) के ध्यान में लाना है कि जो परिवीक्षाधीन अवधि में हैं और अप्राधिकृत अनुपस्थिति पर लगातार बने हुए हैं, उनके लिए एक विस्तृत समाप्ति सूचना, इन कर्मचारियों द्वारा बैंक को प्रस्तुत पते पर पहले ही जारी की गई है. सूचना से संबंधित उद्धरण निम्न प्रकार है :

''नियुक्ति पत्र से संबंधित खण्ड लागू करते हुए, आपको एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आपकी सेवाओं को, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 दिनों के बाद से प्रभावी रूप से समाप्त/ सेवा मुक्त किया जाएगा।''

दिनांक : 11.07.2018
स्थान : बेंगलूर

हस्ताक्षरित /–
महा प्रबंधक (कार्मिक)
कार्मिक विभाग, प्रधान कार्यालय

बी एच ई एल BHEL
Bharat Heavy Electricals Limited
UNIT : TIRUCHIRAPPALLI
सेफ्टी शूज़ (SAFETY SHOES) हेतु आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता
बीएचईएल तिरूच्चिराप्पल्लि द्वारा सेफ्टी शूज़ (Safety Shoes) की आपूर्ति हेतु सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले एम.ए.ई आपूर्तिकर्ताओं (निर्माताओं) से दो भागों में मुहरबंद निविदाएं (केवल ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से) आमंत्रित की जाती हैं, जिसके लिए टेंडर दस्तावेज़ एवं पूर्ण विवरण बीएचईएल वेबसाइट https://www.bhel.com (Tender Notifications Page) पर संदर्भ संख्या NIT_39724 से या https://eprocure.gov.in पर संदर्भ संख्या 2018_BHEL_338135_1 से डाउनलोड किया जा सकता है। बीएचईएल द्वारा अपेक्षित वस्तुओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया https://supplier.bhel.in पर हमेशा खुली है। भावी आपूर्तिकर्ता (एमएसई एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) संबंधित इकाई में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
टेंडर हेतु सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ठ/संशोधन/समयावधि विस्तार/स्पष्टीकरण आदि केवल उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे और अन्य किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। बोलीदाता स्वयं को अपडेट करने हेतु नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट देखें।
DGM / MM / PSS, BHEL, Tiruchirappalli – 620 014 (TN)
Ph.: 0431-257 7645; Fax: 2520719; email: pgavictor@bhel.in

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement.)
AVON Furniture
AVON MOLDPLAST LIMITED
(Avon Moldplast Limited was originally incorporated as "Nira Investments Private Limited" on July 01, 1996 under the Companies Act, 1956 with a Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Karnataka, Bangalore. Thereafter a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name from "Nira Investments Private Limited" to "Nira Marketing Appliances Private Limited" was issued by the Registrar of Companies, Karnataka, Bangalore on August 01, 2002. Thereafter a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name from "Nira Marketing Appliances Private Limited" to "Avon Moldplast Private Limited" was issued by the Registrar of Companies, Karnataka, Bangalore on November 11, 2002. Thereafter, the registered office of our Company was shifted from State of Karnataka to State of Uttar Pradesh and a certificate of registration of the order of the Regional Director, South East Region, dated January 17, 2018, confirming transfer of the registered office from one state to another was issued by the Registrar of Companies, Kanpur on February 15, 2018. Subsequently our Company was converted into a Public Limited Company and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion of the Company to public limited company in the name of the "Avon Moldplast Limited" was granted by the Registrar of Companies, Kanpur on March 01, 2018.)
Corporate Identification Number (CIN) of the Company is U25200UP1996PLC101013.
Regd. Office: A-7/36-39, South of G. T. Road Industrial Area, Electrosteel Casting Compound, Ghaziabad 201009, Uttar Pradesh;
Tel: +91-120-4376091; **E-mail:** cs@avonmpl.com; **Website:** www.avonmpl.com;

THE ISSUE
PUBLIC ISSUE OF 884,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF AVON MOLDPLAST LIMITED (THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 51 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 41 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS. 450.84 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH 46,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 51 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS. 23.46 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. ISSUE OF 838,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 51 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS. 427.38 LACS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.17% AND 25.75% RESPECTIVELY OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.
THE ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER XB OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2009 (as amended from time to time)
For further details see "Issue Information" beginning on page 201 of the Prospectus
THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10 EACH.
THE ISSUE PRICE IS RS. 51 PER EQUITY SHARE AND IS 5.10 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

ISSUE — OPENS ON: Thursday, July 12, 2018 — CLOSES ON: Wednesday, July 18, 2018
ASBA* — Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it.
* Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

ALL POTENTIAL INVESTORS ARE MANDATORILY REQUIRED TO PARTICIPATE IN THE ISSUE THROUGH AN APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") PROCESS PROVIDING DETAILS ABOUT THE BANK ACCOUNT WHICH WILL BE BLOCKED BY THE SELF CERTIFIED SYNDICATE BANKS ("SCSBs") FOR THE SAME AS PER THE SEBI CIRCULAR CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 DATED NOVEMBER 10, 2015. FOR DETAILS IN THIS REGARD, SPECIFIC ATTENTION IS INVITED TO "ISSUE PROCEDURE" ON PAGE 208 OF THE PROSPECTUS. IN CASE OF DELAY, IF ANY IN UNBLOCKING/REFUND, OUR COMPANY SHALL PAY INTEREST ON THE APPLICATION MONEY AT THE RATE OF 15% PER ANNUM FOR THE PERIOD OF DELAY.

PROMOTERS OF THE COMPANY
MR. SUSHIL KUMAR AGGARWAL, MRS. ANITA AGGARWAL AND MR. SAHIL AGGARWAL

LISTING
The Equity shares Issued through this Prospectus are proposed to be listed on SME platform of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") ("NSE EMERGE"). Our Company has received an in-principle approval letter dated May 30, 2018 from NSE for using its name in the Issue document for listing of our shares on the NSE EMERGE. For the purpose of the Issue, the Designated Stock Exchange will be the National Stock Exchange of India Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI)
Since the Issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Draft Offer Document has not been filed with SEBI. In terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 193 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)
It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE".

LEAD MANAGER TO THE ISSUE
Turnaround Corporate Advisors Private Limited
714, Vishwadeep Building, Plot No. 4, District Centre, Janakpuri, New Delhi- 110058
Tel: +91-11-45510390
E-mail: info@tcagroup.in
Investor Grievance Email: complaints@tcagroup.in
Website: www.tcagroup.in
Contact Person: Mr. Heemadri Mukerjea
SEBI Registration No.: MB/INM000012290

Mas Services Limited
T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Tel :+91-11-26387281,82,83;
Fax :+91-11-26387384
E-mail: info@masserv.com
Investor Grievance Email: info@masserv.com
Website: www.masserv.com
Contact Person: Ms. Anjali Agarwal
SEBI Registration No.: INR000000049

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Mr. Shikhar Agarwal
Avon Moldplast Limited
A-7/36-39, South of G. T. Road Industrial Area, Electrosteel Casting Compound, Ghaziabad 201009, Uttar Pradesh
Tel: +91-120-4376091; Email: cs@avonmpl.com, Website: www.avonmpl.com
Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar in case of any pre-Issue or post- Issue related problems, such as non-receipt of letters of allocation, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary accounts or unblocking of ASBA accounts etc.

CREDIT RATING
This being a public issue of equity shares, no credit rating is required.

TRUSTEES
This being an issue of Equity shares, appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING
Since the Issue is being made in terms of Chapter XB of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013
Contents of the Memorandum of the Company as regards its Objects: Investors are requested to refer to clause III of the Memorandum of Association of the Company for the main objects and other objects of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For details see the section "**Material Contracts and Documents for Inspection**" on page 273-274 of the Prospectus.
Liability of Members as per MoA: The Liability of Members is Limited.
Capital Structure: Authorized Share Capital: Rs. 50,000,000 divided into 5,000,000 Equity Shares of Rs.10 each; Issued, Subscribed and Paid-Up Capital before the Issue: Rs. 23,700,000 divided into 2,370,000 Equity Shares of Rs.10 each fully paid up; Proposed Post Issue Paid up capital: Rs. 32,540,000 divided into 3,254,000 Equity Shares of Rs.10 each fully paid up

ORIGINAL SIGNATORIES		CURRENT PROMOTERS	
Name of the Signatories to the MoA	Number of Shares subscribed	Name of the Current Promoters	Number of Shares
Mrs.Anita Aggarwal	100	Mr.Sushil Kumar Aggarwal	780,000
Mrs.Nirmala Aggarwal	100	Mrs. Anita Aggarwal	690,000
Mrs.Sunehri Devi	100	Mr.Sahil Aggarwal	450,000
Total	300	Total	1,920,000

Note: Currently the Promoters collectively with other members of the Promoters Group are holding 2,220,000 Equity Shares of Rs. 10/- each.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS
Application Forms may be obtained from the Registered Office of our Company i.e. Avon Moldplast Limited, the Lead Manager to the Issue i.e. Turnaround Corporate Advisors Private Limited, the Registrar to the Issue i.e. MAS Services Limited and the Bankers to the Issue i.e. Kotak Mahindra Bank Limited. The Application Forms may also be downloaded from the website of the National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com. Application supported by Block Amounts forms shall be available with the designated branches of Self Certified Syndicate Banks, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS
Investors shall note that Investment in Equity Shares involves degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the SEBI's website (www.sebi.gov.in), website of the Company (www.avonmpl.com), the website of the Lead Manager to the Issue (www.tcagroup.in) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA)
Investors shall apply through the ASBA process. The Investors are required to fill the ASBA Form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA Form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.
Capitalised terms used herein and not specifically defined herein shall have the meaning given to such terms in the Prospectus.
For Avon MoldplastLimited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Sushil Kumar Aggarwal)
Chairman & Whole Time Director
Date : July 10, 2018
Place : Ghaziabad

Avon Moldplast Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kanpur. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Lead Manager to the Issue at www.tcagroup.in and website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.avonmpl.com.
Investors should note that investment in Equity Shares involves high degree of risks. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" of the Prospectus, which has been filed with RoC.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be offered or sold within the United States (as defined in Regulations under the Securities Act) or to, or for the account benefit of "U. S. Person" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act.